ras and how many of these cases are pending for more than (i) five years and (ii) ten years respectively;

(b) is there any proposal to increase the number of benches/judges at these and other courts for the speedy disposal of pending cases; and

(c) whether Government is considering any proposal to set up special courts or benches for speedy trial of economic offences like tax evasion etc.?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) A statement containing the requisite information is attached.

(b) There is a proposal to increase the number of judges in the Delhi High Court.

(c) It is for the Chief Justices of the concerned High Courts to set up special benches according to need.

Statement

The number of Civil and Criminal cases pending at the High Courts of Delhi, Bombay, Calcutta and Madras on 31st December, 1977.

Name of the High Courts	No. of cases pending on 31-12-1977					
	Civil			Criminal		
	Total	More than 5 years	More than 10 years	Total	More than 5 years	More than 10 years
Delhi	25,051	6,554	427	1,536	35	2
Bombay	47,996	8,333	614	4,596	1	..
Calcutta	64,645	17,544	6,292	5,408	280	4
Madras	46,480	1,823	74	5,283	15	1

हाजीपुर वेन्डर एसोसिएशन

5440. **श्री राम विलास पासवान:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की हाजीपुर वेण्डर एसोसिएशन गत बीस वर्षों से फल बेचने का काम कर रही थी ;

(ख) क्या इस एसोसिएशन का लाइसेंस 31 मार्च, 1977 को रद्द करके उसे एक व्यक्ति को दे दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) मेसर्स एन० ई० वेण्डर्स कोपरेटिव सोसाइटी लि० हाजीपुर के पास 12-9-57 से 31-3-1977 तक हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर फल बेचने का ठेका था ।

(ख) सोसाइटी ने 31-3-1977 तक काम किया और उसके बाद ठेका 1-4-1977 से दो ठेकेदारों को दिया गया था ।

(ग) सोसाइटी एक सहकारी समिति के रूप में काम नहीं कर रही थी लेकिन उसने ठेका 40 व्यक्तियों को आगे उप-ठेके पर दे रखा था जो अपने कार्य की व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से कर रहे थे। हाजीपुर के सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार को जब यह मामला भेजा गया तब उन्होंने यह पाया कि समिति यह अनियमितता बरत रही थी। चूंकि यह समिति उपनियमों के अनुसार काम नहीं कर रही थी इसलिए ठेका समाप्त कर दिया गया था।

कुतुब एक्सप्रेस को जबलपुर तक बढ़ाना

5441. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने जबलपुर से दिल्ली तक सीधी गाड़ी उपलब्ध कराने के लिए कुतुब एक्सप्रैस को जबलपुर तक बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस गाड़ी का नाम बदल कर नर्मदा एक्सप्रैस अथवा 'मार्बल राक्स" अथवा 'संगमरमर एक्सप्रैस' अथवा 'संस्कारधानी एक्सप्रैस' रखने का है ;

(ग) क्या सरकार इस गाड़ी को जबलपुर से दिल्ली पहुंचने की प्रस्तावित अवधि को 17 घण्टे से घटा कर 15 घण्टे कर देने के लिए कतिपय कदम उठायेगी; और

(घ) क्या इस गाड़ी को बरास्ता बीना चलाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) हां। (क) जीहां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस गाड़ी के यात्रा समय को कम करने के प्रश्न की समीक्षा की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Government Control over Registered Societies

5442. SHRI BHAGAT RAM: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government exercise any control over the societies registered under the Registration of Societies Act, 1860;

(b) whether the societies registered under the said Act are subject to the judicial review in so far as their administrative, financial and other functions are concerned;

(c) how many of such societies are fully or partly financed by the Government; and

(d) is there any proposal to regulate the working of societies owned or financed by Government so as to make them more objective, meaningful and accountable and whether there is any proposal to amend the Registration of Societies Act, 1860 which is not in consonance with the present circumstances?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) to (d). The Societies Registration Act, 1860 is administered by State Governments and the Central Government is not concerned with the affairs of the societies registered under this Act except to the extent of their application to Union Territories. The Central Government does not exercise any control over the working of these Societies, nor there is any such proposal under consideration. As a